भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन का उद्घाटन भाषण*

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री विद्यासागर जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, मुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आरबीआई के मेरे साथियो, देवियो और सज्जनो।

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अस्सी वर्ष पूरे कर लिए हैं। आदमी के जीवन में अस्सी वर्ष काफी लंबा समय होता है। दक्षिण भारत में जो व्यक्ति अस्सी वर्ष पूरा कर लेता है उसके लिए सताभिषेकम नाम से समारोह मनाया जाता है। तो एक तरह से आज हम भारतीय रिज़र्व बैंक का सताभिषेकम मना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, आज तो केवल हमारे सफर की शुरुआत का एक पड़ाव है।

रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, तब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। लेकिन, रिज़र्व बैंक निश्चित ही कोई ब्रिटिश संस्था नहीं थी, और यह संस्था शुरू से ही भारत के आर्थिक हितों के लिए काम करती रही है।

रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभा का पोषण भी किया है। 1943 में, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, रिज़र्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनका वित्तीय कौशल बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जिन समस्याओं का सामना किया उनमें से एक समस्या यह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन के कारण भारत पर कर्ज का जो बोझ बन गया था उससे किस प्रकार सम्मानपूर्वक और अटल इरादे के साथ निपटा जाए।

रिज़र्व बैंक का सौभाग्य रहा है कि पिछले वर्षों के दौरान ऐसे बहुत से बेहतरीन नेतृत्व उसे प्राप्त हुए हैं। यह इस बात का भी प्रतीक है कि सरकार केंद्रीय बैंक के मजबूत होने को कितना महत्व देती है। पूर्व गवर्नरों एवं उप गवर्नरों की सूची भारतीय आर्थिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची रही है, जो इस प्रकार है - बेनेगल रामा राव, एम. नरसिम्हम, डॉ. आई. जी. पटेल, डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. रंगराजन, डॉ. बिमल जालान, डॉ. वाई.वी. रेड्डी एवं डॉ. सुब्बाराव जैसे गवर्नर रहे जिन्हें एस.एस. तारापोर, वेपा कामेसन, डॉ. राकेश मोहन, श्यामला गोपीनाथ, ऊषा थोरात एवं डॉ. सुबीर गोकर्ण जैसे उप गवर्नरों का बढ़िया सहयोग प्राप्त हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक का बोर्ड भी बेहतरीन बोर्ड रहा है, जिसे सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और येज़दी मालेगाम जैसी हस्तियों ने मार्गदर्शन प्रदान किया है।

सबसे रोचक बात यह है कि बहुत से गवर्नर प्रशासनिक सेवाओं से रहे हैं। सिर्फ एक, एम. नरसिम्हम ही ऐसे गवर्नर थे जो भारतीय रिज़र्व बैंक से ही थे। फिर भी, सभी गवर्नर यह समझते थे कि रिज़र्व बैंक की भूमिका देश का वित्तीय विकास करते हुए इसकी मौद्रिक और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है। सरकार तथा बैंक के बीच, उनके अपने दृष्टिकोण एवं जोखिम के प्रति नज़रिये को ध्यान में रखते हुए, हमेशा से स्वस्थ संवाद होता रहा है। इतिहास गवाह है कि बाद की आने वाली सरकारों ने रिज़र्व बैंक की विवेकपूर्ण सलाह की हमेशा सराहना की है।

बीते वर्षों के दौरान, रिज़र्व बैंक को बहुत से मुद्दों का सामना करना पड़ा। इनमें से, निश्चित रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन, खाने-पीने की चीजों की कमी, तेल की कीमतों एवं युद्ध जैसे कारणों से उत्पन्न होने होने वाले मूल्य दबावों के बावजूद रिज़र्व बैंक ने बीते समय में सराहनीय कार्य किया है।

रिज़र्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता वित्तीय क्षेत्र का विकास करना रही है। नई संस्थाओं की स्थापना करने, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने, बाजार का विकास करने एवं वित्तीय समावेशन का विस्तार करने में भारतीय रिज़र्व बैंक का बहुत अधिक योगदान रहा है।

आने वाले वर्षों में, बैंकिंग जगत में बहुत सी नई संस्थाएं आएंगी, जैसे कि भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और संभवतः डाक बैंक, जो इस समय मौजूद यूनिवर्सल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा विभिन्न प्रकार की गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रौद्योगिकी के प्रयोग का भी बहुत विस्तार हो चुका है।

एक जमाना था जब खातों के लेनदेन को लेजरों में हाथों से दर्ज किया जाता था और कंप्यूटर शब्द के प्रयोग मात्र से यूनियन हड़ताल करने लगती थीं। आज हालत यह है कि कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को सभी बैंकिंग संबंधी लेनदेन की सुविधा मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध करा दी है। इसमें न तो बैंक शाखा में जाना पड़ता है और न ही कलम से कुछ लिखना पड़ता है, और आपका काम हो जाता है।

* 2 अप्रैल, 2015 को मुंबई में आयोजित वित्तीय समावेशन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन का भाषण।

हमारा उद्देश्य स्वामित्व और संस्थाओं से न्यूट्रल होकर, टेक्नोलॉजी में बिना किसी भेदभाव किए प्रतिस्पर्धा के लिए मैदान तैयार करना है। जैसे-जैसे बैंक सूचना प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने तथा लेनदेन की लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, नियर फील्ड कांटैक्ट पेमेंट्स जैसी नई प्रौद्योगिकी प्रयोग में आएंगी ताकि वित्तीय सेवाओं का विस्तार सभी लोगों तक हो सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित की गई सबसे आधुनिक भुगतान प्रणाली इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने साइबर-पर्यवेक्षण की शुरुआत कर दी है और साइबर-सुरक्षा की निगरानी भी करता है।

हमें उन जोखिमों का प्रभाव कम करने के लिए बाजारों को विकसित भी करना है जो बैंकों या निगमों में अक्सर विद्यमान होते हैं। इस मामले में भी हमारा पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है। बहुत से विकासशील देशों की सरकारें सिर्फ विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए मजबूर हैं, किंतु रिज़र्व बैंक ने रुपया आधारित चलनिधि युक्त सरकारी बांड बाजार को विकसित किया है और आज सरकार 40 वर्षीय बांड जारी करने में सक्षम है। हमारे सरकारी बांड खरीदने के लिए विदेशी निवेशकों में उत्सुकता है और विदेशी संस्थाएं रुपए मूल्यवर्ग में बांड जारी करने के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। रुपया, वास्तव में अब अंतरराष्ट्रीय रूप ले रहा है। हमने नए उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया है। हाल ही में प्रारंभ की गई ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाएं विदेशी मुद्राओं का बेहतरीन कारोबार कर रही हैं।

परन्तु हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए देश को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और हमारे बहुत से बैंकों का इसमें पहले से बहुत अधिक एक्सपोजर हो चुका है। आधारभूत संरचना से जुड़ी बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं ने भी बहुत अधिक कर्ज ले रखा है। लिवरेज के प्रति वित्तीय प्रणाली काफी अनुकूल रही है और रिज़र्व बैंक ने इसका पर्याप्त विरोध नहीं किया है। आधारभूत संरचना के लिए वित्त हेतु ज़ोर देते समय वित्तीय स्थिरता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलकर, हमें जोखिम पूंजी के नए स्रोतों का विकास करने की जरूरत है ताकि आधारभूत संरचना संबंधी जरूरतों का वित्तपोषण मध्यम लिवरेज के साथ किया जा सके सके और हम प्रणाली को डीलिवरेज करने में भी मदद कर सकें।

शायद एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती, वित्तीय सेवाओं को हर व्यक्ति के दरवाजे तक और प्रत्येक छोटे-छोटे कारोबार तक पहुंचाना है। पहले जो प्रयास किए गए हैं उससे हमें थोड़ी ही सफलता मिल सकी है, गरीब लोग अभी भी बैंक शाखाओं से बहुत दूर हैं या वहां जाने में वे बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं।

प्रधान मंत्री जन धन योजना एवं मुद्रा बैंक जैसे सरकारी उपायों के साथ ही साथ नई प्रौद्योगिकी, नए संस्थानों एवं सीधे लाभ अंतरण जैसी नई प्रक्रियाओं के कारण मुझे यकीन है कि हमारा देश गरीबों और छोटे लोगों को विकल्प और अवसर उपलब्ध कराते हुए उनको समर्थ बना सकता है। बदले में, रिज़र्व बैंक को बेहतर उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता साक्षरता सुनिश्चित करना होगा।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आज रिज़र्व बैंक को सम्मान मिल रहा है तो इसका कारण यह रहा है कि हजारों लोगों ने बैंक के लिए वर्षों तक पूरी क्षमता और समर्पण भाव से कार्य किया है। मैं इन अनेक लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। रानी धुर्वे जो भोपाल कार्यालय में उप महाप्रबंधक हैं, इन्होंने जाली ईमेल एवं अत्यधिक ब्याज दरों जैसे विषयों पर अनेक फिल्में, किताबें, एवं नुक्कड़ नाटिकाएं तैयार की हैं ताकि लोगों को शिक्षित और सतर्क किया जा सके। निर्मला पटनायक जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक महाप्रबंधक हैं, इन्होंने सरकारी विभागों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से निधियों के अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को सक्षम बनाया है। इस प्रकार से, सरकार एक ही दिन में इन प्रणालियों का महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता बन गई है। इन दोनों अधिकारियों ने सामान्य रूप से अपेक्षित कर्तव्य से अधिक का निर्वाह किया है। बैंक में बहुत से अन्य लोग भी इसी प्रकार से कर्तव्य का निर्वाह करते हैं।

रिज़र्व बैंक का सम्मान इसकी सत्यनिष्ठा के लिए भी किया जाता है। मेरे लिए आज यह बड़े गर्व की बात है कि जब कोई हमारे कार्यालय में विनियम (रेग्युलेशन) बदलने के लिए हमसे बात करने आता है तो पैसे लेकर नहीं आता है बल्कि यह तर्क लेकर आता है कि इसके लिए सही क्या है।

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मजबूत राष्ट्रीय संस्थाएं तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार की मज़बूत मौजूदा संस्थाओं को बाहर से पालन-पोषण किया जाना चाहिए और अंदर से इनका निरंतर नवीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुमूल्य संस्थाएं बहुत कम हैं। इस महान संस्था के 81वें वर्ष में मैं अनुरोध करता हूं कि हम सभी स्वयं को पुनःसमर्पित करें ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्र की समृद्धि एवं सभी के लिए आर्थिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अपना प्रयास जारी रख सके। इस समारोह में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।